खण्ड–07 सत्र–01 (भाग–03) / अंक–05

सोमवार 23 मार्च, 2020 / 03 चैत्र, 1942 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सातवीं विधान सभा

पहला सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–07 (भाग–3) में अंक 05 सम्मिलित है।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन
सचिव
C. VELMURUGAN
Secretary

एम.एस. रावत
उप सचिव (सम्पादन)
M.S. RAWAT
Deputy Secretary(Editing)

विषय–सूची

सत्र – (1) (3) सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 03 चैत्र 1942 (शक) अंक– 05

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	3
2.	श्रद्धांजलि	4
3.	शोक संवेदना	6
4.	सदन में अव्यवस्था	8
5.	आर्थिक सर्वेक्षण तथा आउटकम बजट	15
6.	वार्षिक बजट (2020–2021)	16
7.	अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण (वित्त वर्ष 2019–20)	46
8.	विनियोजन (संख्या–1) विधेयेयक, 2020	49
9.	अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण विचार एवं पारण (2020–21)	51
10.	विनियोजन (संख्या– 2) विधेयक, 2020	57
	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	59

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही[1]

सत्र–(1)(3) सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 03 चैत्र, 1942 (शक) अंक–05

दिल्ली विधान सभा
सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

1	श्री अखिलेशपति त्रिपाठी	10	श्री प्रहलाद सिंह साहनी
2	श्री अभय वर्मा	11	श्री प्रकाश जारवाल
3	श्री अनिल कुमार बाजपेयी	12	श्री ऋतुराज गोविन्द
4	श्री अब्दुल रहमान	13	श्री राजेश ऋषि
5	श्री अजय कुमार महावर	14	श्री शिव चरण गोयल
6	श्री जितेन्द्र महाजन	15	श्री एस.के. बग्गा
7	श्री महेन्द्र गोयल	16	श्री विजेन्द्र गुप्ता
8	श्री महेंद्र यादव	17	श्री विशेष रवि
9	श्री मोहन सिह बिष्ट	18	श्री विजेन्द्र सिंह कादयान

1 www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही[1]

सत्र–(1) (3) सोमवार, 23 मार्च, 2020/03 चैत्र 1942 (शक) अंक–05

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम्)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण!

सातवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा ऐडजेस्टमेंट आज विधायकों को करनी पड़ेगी; कोरोना के कारण थोड़ा दूरी बनाकर बैठाने की व्यवस्था की गयी है। आप सबकी सेहत, समाज की सेहत के लिए आप सब थोड़ा सा इसमें ऐडजेस्ट करेंगे। कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है।

श्रद्धांजलि

जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च, 1931 को शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरू ने देष के लिए हंसते–हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन तीनों की शहादत अनमोल थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उन शहीदों ने अपने छोटे से जीवनकाल में क्रांति की जो मषाल जलायी, वह आज भी हमें प्रेरणा रूपी रोषनी दिखा रही है। उनका देष के लिए त्याग, समर्पण और संघर्ष हमेषा याद रखा जाएगा। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरू ने अपने बलिदान से ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखा है जो आज भी हर भारतीय नागरिक को

1 www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

देषभक्ति की भावना से ओत–प्रोत कर देता है। शहीदों के बलिदान के कारण ही हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से वीर शहीदों की शहादत को नमन करता हूं। साथ ही माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जिन्होंने आज श्रद्धासुमन न अर्पित किए हों, सदन के बाद कृपया श्रद्धासुमन अवष्य अर्पित करें।

शोक संवेदना

माननीय सदस्यण!

आपको ये जानकर दुःख होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में शनिवार दिनांक 21 मार्च, 2020 को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गये और 15 जवान घायल हो गये। शहीदों में जिला रिजर्व पुलिस बल और स्पेषल टास्क फोर्स के जवान शामिल हैं। ये घटना अत्यंत दुखद है। देष की आंतरिक सुरक्षा के लिए इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। सुरक्षा में तैनात जवान अपने प्राणों की बाजी लगाकर शहीद हो रहे हैं। एक जवान के शहीद होने से एक पूरा परिवार दुःख के सागर में डूब जाता है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और ईष्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण!

जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की बीमारी के कारण पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है। विष्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में अब तक 2,94,110 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और 12,944 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के 187 देष इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक भारत में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं तथा 60 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सहित 12 राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है।

मैं जनता से अपील करता हूं कि अपने घर से बाहर न निकलें क्योंकि अब ये हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। केन्द्र और राज्य सरकारें लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं। लेकिन जनता के सहयोग के बिना इस आपदा से नहीं निबटा जा सकता।

मैं ईष्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें इस संकट से निपटने की शक्ति प्रदान करे और पूरी दुनिया तथा भारत की जनता को सुरक्षित रखे।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

सदन में अव्यवस्था

माननीय अध्यक्षः ओम शांति–षांति–शांति।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिधूड़ी जी आज केवल विषय...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः सर, जो परिस्थिति है, वो तो मैं समझ रहा हूं। मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरा केवल ये कहना था कि जो एक डिसीजन हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं केवल दो मिनट आपके लूंगा, दो मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः करिए–करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की पहली विधान सभा के आप भी मेंबर थे, मैं भी मेंबर था और शोएब इकबाल साहब भी मेंबर थे और फिर इस विधान सभा का जो पहला बजट सत्र था, वो 7 मार्च, 1994 को शुरू हुआ और 11 अप्रैल, 1994 को समाप्त हुआ। 21 सीटिंग्स हुई। मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि... मुझे मालूम है कि देष की परिस्थिति ठीक नहीं है लेकिन मैं इतनी प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि जैसे ही इस कोरोना वायरस बीमारी पर काबू पा लिया जाए तो आप जो है एक अलग से सेषन जरूर बुलवाएं और उसमें कम से कम 15 सीटिंग्स हों जिससे कि मेंबर्स क्वेष्चन लगा सकें, सरकार से जानकारी हासिल कर सकें और जरूरी मुद्दों को उठा सकें।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः दूसरी बात ये है कि मैं देष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को, दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री अनिल बैजल जी को और दिल्ली के मुख्य मंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस कोरोना वायरस बीमारी पर काबू पाने के लिए जो उनके द्वारा उपाय किए गये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसके साथ–साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं ...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, हो गया, प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः एक सफाई कर्मचारी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो दस्ताने हाथ में पहनकर और मास्क लगाकर अकेला सड़क के ऊपर सफाई कर रहा है। जहां प्रधानमंत्री जी का, उपराज्यपाल महोदय का, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं तो हम उस सफाई कर्मचारी का भी अभिनंदन करें और मेरी इतनी प्रार्थना है कि सफाई कर्मचारियों का जो बकाया वेतन है या जो उनको नियमित करने वाला मामला अभी पेंडिंग पड़ा है, सरकार बकाया वेतन को भी देने की कृपा करे।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, आपने दो मिनट...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः और इसके साथ–साथ मैं ईष्वर से प्रार्थना करता हूं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब नहीं बिधूड़ी जी, प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ईष्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी से

परमात्मा सभी देषवासियों को और दुनिया को निजात दिलाये और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम सभी हाउस के मेंबर्स जो हैं, इसके लिए खड़े होकर हम प्रार्थना करें।

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया, वो हो गया, हो गया प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आपने मुझे समय दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मेरी तरफ से आया है, आप जरूर कुछ दिनों के बाद जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो आप जरूर कम से कम हाउस बुलायेंगे जिस पर 15 सीटिंग्स हों और दिल्ली की समस्याओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हो सके।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, अब रिपीट कर लिया, आपने रख दी अपनी बात।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी...

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपने रख दी अपनी बात।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हमारे मुख्य मंत्री की जो छवि है ना, उनको कार्यकर्ता कहते हैं कि...

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिधूड़ी जी, अब बैठिए प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः उनकी एक छवि है कि वो आरटीआई के...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, अब देखिए समय...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मुख्यमंत्री जी की...

माननीय अध्यक्षः नहीं, बिधूड़ी जी प्लीज,....

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मुख्यमंत्री जी, की छवि है...

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, भाषण नहीं, आपने बोल दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः कि वो आरटीआई के जन्मदाता हैं।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, अब मैं, प्लीज...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब बिधूड़ी जी जो बोल रहे हैं, इसको डिलीट कर दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः डिलीट करें प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बिष्ट जी, अब छोड़ दीजिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आज, आज का, नहीं, मैं कोई बात नहीं सुन रहा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने बोल दिया, मैंने रूलिंग दे दी है, मैंने रूलिंग दे दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। मैंने रूलिंग दे दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां, मैंने रूलिंग दे दी है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बिष्ट जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रूलिंग दे रहा हूं, मैं कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं रूलिंग दे रहा हूं, मैं रूलिंग दे चुका हूं बिष्ट जी, मैं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बैठ जाइए आप। प्लीज, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बिष्ट जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, सदन को... आप राजनीतिक विषय को ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पूरा देष इस वक्त परेषानी में है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बाहर, नियम को छोड़ दीजिए। बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अध्यक्ष की रूलिंग ये है, अध्यक्ष जिसको चाहेंगे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब मैं बता देता हूं, पहले बैठिए आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हां, मैं रूलिंग बोल देता हूं आपको।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब कोई नहीं। प्लीज। माननीय सदस्यगण,...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए देष जो है इस वक्त गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। प्रत्येक नागरिक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। हम इसको... मैंने पढ़ लिया है, आपने जो बोला है। मैंने पूरा पढ़ लिया है। मैं बोल दूं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः टोटल राजनीति से प्रेरित है। बैठ जाइए, टोटल राजनीति से प्रेरित है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं। 293, नहीं। आप 293 पढ़ लीजिए, 110– का।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं बोल देता हूं, किसी संकल्प या प्रश्न या किसी अन्य विषय की स्वीकृति, अस्वीकृति देने के बारे में अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। पढ़ लीजिए, 293 में। आप पुराने सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब छोड़ दीजिए बिष्ट जी। मैंने बोल दिया, बता दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। अब मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20... देश में तेजी से फैलती महामारी; कोरोना वायरस के कारण एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है हमारा देश। माननीय मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री के परामर्श के बाद हमने बजट सत्र को आज ही समाप्त करने का निर्णय लिया है। निर्णय को आज हुई बैठक में कार्यमंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। तदानुसार बजट तथा संबंधित विषय आज लिया जाएगा। कार्यसूची में सूचीबद्ध विषय के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं दिया जाएगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम–से–कम समय में सदन सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग दें। धन्यवाद।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा आउटकम बजट

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 सदन में प्रस्तुत करता हूं।[2]

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के... अच्छा करिए, प्रस्तुत करिए।

माननीय उप–मुख्यमंत्रीः आउटकम बजट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली का आउटकम बजट 2019–20, दिसम्बर, 2019 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।[3]

माननीय अध्यक्षः हां, प्रस्तुत कीजिए।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः नहीं हो गया... जी, हो गया वो।

माननीय अध्यक्षः बस। टेबल हो गया? ठीक है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः आउटकम बजट जो पिछले साल का था, दिसम्बर, 2019 तक का।

---

2 www.delhiassembly.nic.in व पुस्तकालय में संदर्भ संख्या....आर–20803 उपलब्ध।

3 www.delhiassembly.nic.in व पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20804 उपलब्ध।

वार्षिक बजट (2020–2021)

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2020–21 अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण का वार्षिक बजट प्रस्तुत करें।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार दिल्ली में बनी सरकार का पहला बजट है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सदन में लगातार छठी बार वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में बजट प्रस्ताव रख रहा हूं।

इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने दिल्ली के नागरिकों का विश्वास और भरोसा जीता है। दिल्ली के नागरिकों ने मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले पांच साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर अटूट भरोसा जताते हुए जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है, उससे मेरा मन दिल्ली के अपने प्रिय भाई–बहनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान से भर जाता है।

महोदय, यह बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब, जैसा आपने अभी कहा, भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना, कोविड–19 की महामारी से जूझ रही है। करीब 15 हजार लोग मर चुके हैं। इस महामारी की चपेट में आकर बहुत सारे लोग अभी अस्पतालों में हैं, कोरोन्टाइन में बैठ हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मिलकर इस कोशिश में हैं कि पूरी मानव जाति को इसके प्रकोप से बचाया कर रखा जा सके। मैं बजट के मूल वक्तव्य पर आने से पहले इस सदन की ओर से और सरकार की ओर से उन सभी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को सम्मान अर्पित करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको बचाये रखने में लगे हैं। मैं सरकार की ओर से और सरकार की ओर से सदन और पूरी दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी और जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी, वो उपलब्ध करायी जाएगी।

महोदय, दिल्ली के लोगों ने 2015 में पिछली बार जब हमारी सरकार को चुना था तो हमने दिल्ली को विश्वस्तर का शहर बनाने का वादा किया था। बड़े गौरव और हार्दिक प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। पिछले पांच साल के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिल्ली की पहचान विकास के मॉडल के तौर पर बनी है। आज दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण और आम आदमी के जीवन–स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गये सामाजिक सुरक्षा के उपायों की दिषा में एक नई पहल और एक नई सोच के लिए जाना जाने लगा है।

महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व वाली इस सरकार ने अपने बहुत से चुनावी वादे पूरे किए हैं और शासन–संचालन का एक कुशल मॉडल कायम किया है। आज इसी मॉडल को देशभर में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम से पहचान मिल रही है और सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर से लोग पिछले पांच साल में इस मॉडल को देखने–समझने के लिए दिल्ली में आये हैं।

केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का आधार ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, ये इसका आधार है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि देश में हम पहली बार शिक्षा पे बात नहीं कर रहे। हमारे देश में शिक्षा पे पहले भी काम हुआ है। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान हमने नहीं खुलवाये। देश में बहुत सारे शानदार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हजारों बच्चों को शानदार एजूकेशन मिलती है, ये हमने नहीं शुरू करवाये। शिक्षा पे काम पहले भी हुआ है। लेकिन उसमें एक खामी ये रह गयी कि पांच परसेंट बच्चों को शानदार एजूकेशन और 95 परसेंट बच्चों को कामचलाऊ एजूकेशन का मॉडल इंडिया में डेवलप हुआ। हमने इसी को बदला है। आज दिल्ली में हर बच्चे को, गरीब–से–गरीब आदमी के बच्चे को भी वैसी ही अच्छी शिक्षा देने पर काम हो रहा है जैसा किसी सक्षम परिवार के बच्चे को शिक्षा मिलती है। पिछले पांच साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से साबित हो गया है कि सरकार अगर चाहे तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है वो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या गवर्मेंट स्कूल में, वो चाहे गरीब परिवार से हो या सक्षम परिवार से हो।

अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का दूसरा और सबसे बहुचर्चित आधार है, दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे बहुचर्चित आधार है सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य। चंद लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और बाकी लोगों को कामचलाऊ चिकित्सा व्यवस्था के रहमो–करम पर छोड़ देना इसका मॉडल हमारे सामने पहले था। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक में अच्छा इलाज हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना। दवाइयां उपलब्ध कराना, टेस्ट उपलब्ध कराना और 'दिल्ली के फरिश्ते' जैसी योजनाओं से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को वो चाहे अमीर हों या गरीब, सबकी जान बचाना, इस सबको आज देश भर में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में पहचान मिल रही है और मुझे खुशी है कि देश की कई सरकारें आज इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही हैं।

इसी तरह दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे और देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, पानी उपलबध कराना, फ्री वाई–फाई उपलब्ध कराना, गली–गली में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी लगवाना, अनऑथोराइज्ड कालोनी में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और इन सबसे शहर को विकसित और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाये गये कई ऐसे कदम हैं जिनकी वजह से दिल्ली के आम नागरिक का अपनी सरकार में विश्वास बढ़ा है।

राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों से लेकर गाड़ी और प्रॉपर्टी के कागजों की कॉपी लेने तक में आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के जो धक्के खाने पड़ते थे, उस पीड़ा को मुख्य मंत्री जी ने समझा और इस तरह की 100 से अधिक सेवाओं को डोर–स्टैप डिलीवरी के तहत लोगों को घर पर बैठे उपलब्ध कराया। आज देश के कई राज्य आंशिक तौर पर ही सही लेकिन इस योजना को भी अपने यहां पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरह से दिल्ली में मेट्रो का लगातार विस्तार करके और सड़को पर नई बसें उतार कर जहां एक तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और मजबूत बनाया जा रहा है, वहीं बसों में सीसीटीवी और बस मार्शल लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। और जब

पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित हुआ तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करना भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक ऐसा प्रयोग है जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। आधी आबादी को परिवार और देश की इकॉनामी में भागीदार बनाने के लिए यह कदम महिलाओं को फ्री बस टिकट उपलब्ध कराना, यह कदम आधी आबादी को परिवार और देश की इकॉनामी में भागीदार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सबका भरोसा है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त जो बातें मैंने कही, इन सबका सार ये है कि आज जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो सिर्फ गवर्नेंस का नहीं, इकॉनामी का भी एक मॉडल बनके उभरा है। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज केजरीवाल मॉडल ऑफ इकॉनामी की वजह से मंहगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के बावजूद दिल्ली का आम आदमी मजबूती के साथ खड़ा है। जीएसडीपी के आंकड़े और परकैपिटा इनकम जिनका जिक्र मैं अपने वक्तव्य के अगले हिस्से में करूंगा, इसका प्रमाण है और उसकी वजह साफ है; ईमानदार सरकार के कारण आम आदमी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, व्यापारी को शोषण का सामना नहीं करना पड़ता, सरकार की नीतियों की वजह से भी दिल्ली के लाखों परिवारों में हर महीने हजारों रुपये की बचत हो रही है और इस सब से जो बचा हुआ पैसा है, वो आम आदमी अपने आस–पास के स्थानीय बाजारों में खर्च कर रहा है। जिससे शहर की आर्थिक प्रगति हो रही है। हमने अभी एक सर्वे कराया है जो अभी चल रहा है। हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में उसमें करीब तीन हजार का सैम्पल है; 11 जिलों में कराया गया है, साढ़े तीन हजार का। दिल्ली के उन लोगों का जिनको इन स्कीमों का फायदा मिल रहा है, केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस के तहत जो स्कीम शुरू की गयी और 68 परसेंट लोगों का कहना है कि उन्होंने वो बचा हुआ पैसा, आस–पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट में खर्च किया। 28 परसेंट लोगों का कहना है कि उन्होंने वो पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी या किसी और स्कीम में निवेश किया है। तो 68 परसेंट लोग जो इमिडेट्ली अपने आस–पास की मार्केट में खर्च कर रहे हैं, यही इकॉनामी को बूम करने का, यही दिल्ली के मार्केट को आगे बढ़ाने का एक मॉडल है। नोबल पुरुस्कार

प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और Esther Duflo ने सरकार चलाने के इसी मॉडल को मार्डन सक्सेसफुल इकॉनामी की संज्ञा दी है अध्यक्ष महोदय।

आर्थिक परिदृश्य

अब मैं दिल्ली के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की एक तस्वीर सदन के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं महोदय, दिल्ली के पास न तो पूर्ण राज्य का दर्जा है और न भूमि संसाधनों पर हमारी सरकार की पहुंच है। इसके बावजूद दिल्ली के मूल आर्थिक घटक बड़े मजबूत हैं। दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद जिसका मैंने जिक्र उस वक्त किया, जीएसडीपी में वर्ष 2019—20 के दौरान 10.48 प्रतिशत की दर से विकास होने की संभावना है यह अपने आपमें एक रिकॉर्ड है 10.48 परसेंट। पिछले साल के, जिससे ये पिछले के 7,74,867 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,56,112 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगी जीएसडीपी।

स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था के 2019—20 के दौरान 7.42 परसेंट की दर से विकसित होने की संभावना है जो पांच परसेंट की ऑल इंडिया ग्रोथ रेट से काफी अधिक है। पिछले पांच साल में जीएसडीपी की वार्षिक... जो पिछले पांच साल की गवर्नेंस थी केजरीवाल मॉडल आफ गवर्नेंस के तहत, आर्थिक जीएसडीपी की वृद्धि दर का औसत 8.18 परसेंट रहा जो कि दिल्ली की आर्थिक स्वास्थ्य की, अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का परिचायक है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019—20 में 3,89,143 रुपये होने का अनुमान है जो 18—19 में 3,58,430 रुपये की थी। उसके मुकाबले 8.57 परसेंट अधिक है। 2015—16 में जब हमारी सरकार सत्ता में आयी थी तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2,70,261 रुपये थी और तब से इसमें 44 परसेंट की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। आज देश भर में देखें तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम ये सब नीचे की तरफ इनका ग्रॉफ जा रहा है और दिल्ली में पिछले पांच साल में 44 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली है, पर कैपिटा इनकम की। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा राजनीतिक दावा नहीं है कोई, ये जीएसडीपी के आंकड़े हैं। ये पर कैपिटा इनकम के आंकड़े हैं, ये हमारे इकॉनामिक सर्वे के आंकड़े हैं और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब तीन गुणा अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, 2019–20 में प्रति व्यक्ति आय आमदनी का राष्ट्रीय औसत 1,34,000 रुपये है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली के योगदान में भी बढ़ोत्तरी हुई है जो हमारा कंट्रीब्यूशन है दिल्ली का 2014–15 के 3.97 परसेंट से बढ़कर 2019–20 में 4.20 परसेंट हो गया है। हालांकि दिल्ली की आबादी देश की कुल जनसंख्या की 1.49 परसेंट ही है। डेढ़ परसेंट लोग दिल्ली के जो मुख्य मंत्री जी भी बार–बार कहते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हम लोग और कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम लोग मेहनती लोग हैं दिल्ली के और ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। उस सबसे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल इकोनॉमी में, वो 4.20 परसेंट है जबकि लोग कुल मिला के डेढ़ परसेंट हैं, 1.49 परसेंट हैं।

अध्यक्ष महोदय अब मैं संशोधित अनुमान 2019–20 के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 2019–20 के संशोधन अनुमान के लिए 54,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जाता है जबकि बजट अनुमान में 60,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी। चालू वर्ष के संशोधन अनुमान की राशि 18–19 में खर्च की गयी 46,246 करोड़ रुपये की राशि से 18.50 अधिक है। स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध खर्च को 2019–20 के बजट अनुमान में स्वीकृत 33,000 करोड़ रुपये से घटाकर 19–20 के संशोधन अनुमान में 32,600 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। बजट अनुमान में योजना परियोजना के तहत स्वीकृत 27,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को बजट अनुमान 19–20 में घटाकर 22,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव है जो 18–19 में 15,625 करोड़ रुपये के खर्च से 42 परसेंट अधिक है।

सरकार का बकाया ऋण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां मैंने पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात कही। मैंने जीएसडी भी बढ़ने की भी बात कही। नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने की बात कही, वहीं इसी सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी आयी जिसने ये माना कि सरप्लस गवर्नमेंट चल रही है। वहीं ये डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का बकाया ऋण 2015–16 के 33,304 करोड़ रुपये से घटकर 18–19 में 32,732 करोड़ रुपये हो गया है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इसी सरकार का ऋण भी नीचे आ रहा है। लोन भी, जो कर्ज है दिल्ली के एक एक आदमी के ऊपर, सरकार के ऊपर, वो भी नीचे आ रहा है। इससे कर संकलन में

सुधार और बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्ज पर निर्भर न रहने जैसे उपायों से बेहतर वित्तीय प्रबंधन का पता चलता है। 2018–19 में हमारी सरकार का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 4.22 परसेंट था जो देश के सभी राज्यों से कम है इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये केजरीवाल मॉडल आफ इकोनॉमी भी है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल मॉडल आफ गवर्ननेंस नहीं, केजरीवाल मॉडल आफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी इसको देखना पड़ेगा कि वित्तीय प्रबंधन अच्छे हैं, जीएसडीपी आगे बढ़ रही है, दिल्ली की ग्रोथ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2019–20 के लिए पूरक अनुदान मांगें[4] प्रस्तुत करता हूं। संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 1,60,815 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की आवश्यकता होगी इसलिए मैं अनुपूरक मांगों के लिए सदन से स्वीकृति का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष बजट अनुमान 2020–21[5] प्रस्तुत करता हूं। मैं अगले वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं और इस वर्ष के लिए कुल 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का प्रस्ताव है जिसमें स्थापना खर्च, ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब 2015 में सरकार बनी थी तो उस वक्त का बजट था 30,000 करोड़ रुपये। केवल छठे बजट तक आते–आते ये 65,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है जिसमें स्थापना खर्च और प्रतिबद्ध देयता, स्थानीय निकायों को अंतरण, भारत सरकार को चुकाया जाने वाला ब्याज और मूलधन, परिवहन, और जल और विद्युत सब्सिडी आदि के 35,500 करोड़ रुपये और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने के लिए 29,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। 65,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में राजस्व खर्च के 48,070 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च के 16,929 करोड़ रुपये शामिल हैं। 65,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 44,100 करोड़ रुपये के हमारे कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से, 1,100 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्तियां। जीएसटी के अंतर्गत कंपनसेशन के 7,800 करोड़ रुपये। 4,141 करोड़ रुपये

4 www.delhiassembly.nic.in व पुस्तकालय में संदर्भ संख्या....आर–20806 उपलब्ध।

5 www.delhiassembly.nic.in व पुस्तकालय में संदर्भ संख्या....आर–20805 उपलब्ध।

स्मॉल सेविंग्स। केन्द्र द्वारा स्पॉसर्ड स्कीम्स; विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं और अन्य प्राप्तियों से मिलने वाले 1,808 करोड़ रुपये। 626 करोड़ रुपये सामान्य केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी में केवल 325 करोड़ रुपये और बकाया राशि हमारी प्रारंभिक क्षेत्र से प्राप्त होगी। 2020–21 में 65,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट 2019–20 के 54,800 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 18.5 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार 2020–21 में स्थानीय निकायों को 6,828 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी जबकि 2019–20 के बजट अनुमानों में इसके लिए 6,380 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। स्थानीय निकायों को कुल वित्तीय सहायता में कर संग्रह में 2,299 करोड़ का हिस्सा, स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1,805 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी और एक बार की पार्किंग चार्जेज आदि शामिल हैं। विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हम 2020–21 में स्थानीय निकायों को 2,724 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव रखते हैं।

महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा रखना चाहूंगा जो अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट का अहम हिस्सा हैं। योजनाएं काफी विस्तृत हैं, मेरी बजट स्पीच में। मैं अनुरोध करूंगा कि बजट स्पीच को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ताकि मैं संक्षेप में उनको सदन के समक्ष रख सकूं।

महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि शिक्षा का कार्य केजरीवाल मॉडल आफ गवर्ननेंस का आधार काम है। दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो पिछले पांच साल में अपने बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती आयी है। पिछले पांच साल में हमने शिक्षा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारे प्रयासों और कठोर परिश्रम का परिणाम है कि आज शिक्षा की वजह से दिल्ली की ख्याति देश विदेश में बढ़ रही है। मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन और शिक्षकों और बच्चों की मेहनत से परीक्षा के परिणाम सुधरे हैं। सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छी स्कूल बिल्डिंग्स में, शानदार वातावरण और शानदार सुविधाओं में बैठकर पढ़ते हैं। उनके लिए लैब, लाइब्रेरी और खेल की सुविधाएं विकसित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जा रहे काम और स्कूलों में दी जा रही षिक्षा की गुणवत्ता का आकलन केवल शानदार इमारतों और अच्छे रिजल्ट से नहीं हो सकता। अगर हमें शिक्षा के माध्यम से देश को वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स देने हैं तो हमें अपने स्कूलों को भी वर्ल्ड क्लास कंपीटीशन में उतारना होगा। हमारी तैयारी है कि हम अपने स्कूलों को और भी अच्छा करें और शिक्षकों को भी अच्छी ट्रेनिंग दें और शिक्षा व्यवस्था में भी वो सब बदलाव करें जो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास कंपीटीशन में मजबूती से खड़ा कर सकें। अब हम इस कदम पर हैं। इसके तहत कुछ योजनाएं, मैंने इस पूरे बजट में रखी हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से मैं उसका संक्षेप में विवरण आपके सामने रख देता हूं; पहला, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली सरकार 2024 में होने वाले पीसा टैस्ट में एजुकेशन को शामिल करेगी। आपकी जानकारी, सदन की जानकारी के लिए पीसा टैस्ट शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है, हर तीन साल के अंतर पर होती है और दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी आगे बढ़ चुके देश हैं, वो इसमें शामिल होते हैं और उसमें इस बात का आकलन किया जाता है कि कोई देश या राज्य 15 साल की उम्र के बच्चों तक को जो शिक्षा दे रहा है, उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर क्या है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल ऐज में नौकरियां मिलती हैं, ग्लोबल ऐज में बिजनेस करते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है तो 2024 में हम अपने शिक्षा विभाग को पीसा के द्वारा आकलन कराएंगे। उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमारा मानना है कि पिछले पांच साल की मेहनत को आगे बढ़ाते हुए और केजरीवाल मॉडल आफ एजुकेशन गवर्ननेंस के जरिए हम दिल्ली को 2024 में दुनिया के एजुकेशन मैप पर स्थापित कर देंगे, ये हमारा भरोसा है। अगले वित्त वर्ष से शिक्षा के लिए बजट प्रस्ताव और हमारी तैयारी इसी बात को ध्यान में रखकर की जा रही है। हमारे शिक्षा में उठाये गये कदमों में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है; हैप्पीनैस, बिल्डिंग आफ क्लासरूम्स के बाद हैप्पीनैस क्लास। यूएस की फर्स्ट लेडी अभी थोड़े दिन पहले आकर गयी। उसके अलावा एंतरप्रेन्योर्स दुनिया भर के और बहुत सारे देशों के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और दुनिया

के बहुत सारे देशों के शिक्षाविद्, उनके एजुकेशन अथॉरिटीज यहां आके हैप्पीनेस क्लास अटैंड करके गयी हैं। एंतरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जिसमें बच्चे केवल नौकरियां ढूंढ़ने वाले न बनें, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ–साथ एक नया पाठ्यक्रम लाया जा रहा है; देशभक्ति का पाठ्यक्रम, तो आप देख सकते हैं कि जो हैप्पीनेस कार्यक्रम है, उसके जरिए हम हर बच्चे को एक संवेदनशील और अच्छा इंसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एंतरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के जरिए हम उसे आत्मविश्वास से भरा हुआ एक प्रोफेशनल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और जो देशभक्ति पाठ्यक्रम होगा, उसके जरिए बच्चे को अपने राष्ट्र, राष्ट्र के लोगों से प्रेम करना और उसको राष्ट्र पर गर्व करना सिखाया जाएगा, इस पर काम होगा।

इस सबके साथ–साथ कुछ और प्रस्ताव हैं बजट में, जैसे इस साल हम अपने सभी बच्चों को, जो सीनियर क्लासिज़ के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अखबार देने की योजना लेकर आये हैं; न्यूज़पेपर, ताकि उन्हें पढ़ने का और अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर जाग्रत होने का एक मुद्दा पैदा हो। इस साल जो वर्तमान वर्ष है जो चल रहा है, हमने 40 हजार स्टूडेंस को अपने रेगूलर कोर्स के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया था। बहुत सक्सेफुल रहा, उसके पहले हमने 25 हजार बच्चों को कराया था। ये कार्यक्रम अब आगे भी चालू रहेगा और हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलग से क्लासेज़ लगायेंगे। उसके लिए 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसी तरह से जो बच्चे स्कूल पास कर चुके हैं और जो किसी कॉलेज में हैं या किसी तरह का स्किल कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरी पर्सनेलिटी डेव्लप्मेंट में, मेरी इंग्लिश में कोई कमी रह गयी तो उनके स्कूल की तरफ से पास कर चुके बच्चों को जो स्कूल छोड़ कर चले गये हैं, उन बच्चों के लिए भी अलग से स्पोकन इंग्लिश और पर्सनेलेटी डेव्लप्मेंट के प्रोग्राम हम अपने स्कूलों में शुरू करेंगे, ऑफ्टर स्कूल ऑवर्स में।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में साढ़े आठ हजार कमरे पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। 12 हजार कमरों का काम लगभग अंतिम चरण में है। इस तरह से 20 हजार कमरे हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर में जुड़ जायेंगे। 2020–21 में इन कमरों को पूरा करने के साथ–साथ मैं 17 नई स्कूल बिल्डिंग्स को बनाने का भी प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ। इसके

साथ–साथ जैसा मैंने कहा कि हमें मॉर्डन वर्ल्ड के लिए स्टूडेंस तैयार करने हैं, सिटीज़न तैयार करने हैं तो हम हरेक क्लासरूम को डिज़िटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने का भी प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। हर स्कूल के हर क्लासरूम को और विशेषकर शुरूआती दौर में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के स्टूडेंटस के लिए ये काम हम इसी साल से शुरू करेंगे और हर स्कूल में पहले ही साल में कम से कम दस क्लासरूम्स को डिज़िटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, इसके लिए प्रस्तावित बजट में 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी स्कूल्स और सभी मुख्यालयों को, सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं शिक्षा के, उनको वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एजुकेशन डॉयरेक्टोरेट और एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस से जोड़ दिया जायेगा ताकि मीटिंग्स में आने जाने में, अलग–अलग चर्चाओं में लोगों का समय ज्यादा न लगे।

स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का काम भी अंतिम चरण में है और इसको जून 2020 तक खत्म कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपने टीचर्स को केम्ब्रिज, फिनलैंड, सिंगापुर, जर्मनी आदि देशों में भेजा, हार्वड में भेजा। अब तक करीब 1365 शिक्षक हमारे विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। हमारे 700 प्रिसिंपल्स ने आई.आई.टी., अहमदाबाद में स्कूल लिडरशिप की ट्रेनिंग ली है। ये सब कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और इसके साथ–साथ कुछ और देशों में अच्छे प्रयोग हुए हैं जैसे ऐस्टोनिया आदि देश हैं, वहां भी हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे।

हर बच्चे के लिए एक स्कूल कार्ड जो उसका बच्चे का होता है, उसी में उसका हैल्थ डेटा भी डालने का काम किया जायेगा। उसको हम हेल्थ कार्ड कहेंगे; बच्चे का हैल्थ कार्ड।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ हमने पीटीएम कराई थीं पिछले बार और उसका खूब स्वागत हुआ था। पहले पेरेंटस जा नहीं पाते थे अपने बच्चे के स्कूल में। अबकी बार से पीटीएम्स तो जारी रहेंगी, रहेंगी, साथ–साथ हम पेरेंटिंग वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे क्योंकि बच्चे के विकास में माता–पिता की भूमिका बहुत होती है और

उनकी अन्डरस्टेंडिंग बनाने के लिए कि अपने घर में जब बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किस उम्र, किस वर्ग की, लड़की पढ़ाई कर रही है, लड़का पढ़ाई कर रहा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, उस समय में उनकी पेरेंटिंग वर्कशॉप होनी बहुत जरूरी है। तो यह विशेष पेरेंटिंग वर्कशॉप्स भी स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से चलायी जायेंगी। साथ–साथ में गुणवत्ता सुधार के लिए क्योंकि जैसा मैं कह रहा था, आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय, कि आज नर्सरी क्लास में जो हमारे सामने बच्चा आ रहा है, वो कायदे में हम बारहवीं... उसको नर्सरी, के.जी. कराते हुए जब बारहवीं क्लास पास करके दुनिया को देंगे तो वो 2034 में दुनिया में निकलेगा, स्कूल से बाहर निकलेगा तो 2034 की दुनिया बदल चुकी होगी। जीने के तौर–तरीकों में, काम करने के तौर–तरीकों में, सीखने के तौर–तरीकों में। तो आज हम उसको अभी से इस पर आधार रखना शुरू करें नर्सरी, के.जी. से ही, इसके लिए हम शिक्षा के बहुत सारे चीजों में बदलाव करना चाहते हैं जिसमें कि बच्चा सिर्फ रटने की जगह समझने की योग्यता हासिल करके स्कूल से निकले। इसके लिए हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं तो जो हमारा नर्सरी से आठवीं तक का पाठ्यक्रम है, उसमें हम इसको अपने सिलेबस को चेंज कर रहे हैं।

उसके साथ–साथ दिल्ली के अपने राज्य बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने बोर्ड हैं, वो कहीं न कहीं रटे हुए ज्ञान की परीक्षा लेने में माहिर हैं लेकिन समझे हुए ज्ञान की परीक्षा लेने की अगर बात करेंगे तो एक नया बोर्ड बनाकर उस पर प्रयोग करेंगे और उसको आगे बढ़ायेंगे। इसलिए एक नये एजुकेशन बोर्ड, दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं।

साथ–साथ में जो दुनिया भर के सर्वे बताते हैं कि तीन से छः वर्ष की उम्र के बच्चों को अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अच्छी क्वॉलिटी की मिल जाती है तो उनका सफलता का स्तर कुछ और ही होता है। हमारे देश में आंगनवाड़ी को छोड़कर तीन से चार, तीन, चार, पाँच वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। के.जी. और नर्सरी भी कुल मिलाकर ए.बी.सी.डी. रटाने के कार्यक्रम हैं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण और नियमित करने के लिए सरकार एक नया कानून लेकर आयेगी ताकि उसको भी ठीक से वहां क्वॉलिटी एजूकेशन दी

जा सके।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि 20 हजार कमरे जोड़ने का काम हो चुका है, 17 नये स्कूल और भी बनेंगे लेकिन अब जब हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने कुछ स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में और ला सकें। अभी हमारे बहुत सारे स्कूल डबल शिफ्ट में चलते हैं। तो इस साल हम करीब 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

हमने स्कूल ऑफ एक्सिलेंस शुरू किए थे जिनको बहुत सफलता मिली है, आने वाले समय में हर ज़ोन में, सरकार के 29 ज़ोन हैं और हर ज़ोन में लगभग पाँच—पाँच स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोले जायेंगे जो अलग—अलग सेक्टर के स्पेशलॉइज़ स्कूल होंगे। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में 145 स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोले जायेंगे, इसका प्रस्ताव में इस सदन में सक्षम रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हॉयर एजूकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में भी काफी प्रगति हुई है मुख्य मंत्री केज़रीवाल जी के नेतृत्व में। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू आदि के नये कैम्पस खोले गये, नये इन्स्टिट्यूशन्स बनाये गए और कुल मिलाकर 16 संस्थान हॉयर एजुकेशन के पिछले पाँच साल में शुरू किए गये। स्किल सेंटर, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर इसके अलावा शुरू किए गये। पिछले कार्यकाल में अंतिम सत्र में इसी विधान सभा से दो नये विश्वविद्यालय का बिल पास किया गया था। ये दोनो विश्वविद्यालय दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली स्किल एवं एंतरप्रेन्योरषिप यूनिवर्सिटी, ये दोनों इस साल से काम करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ—साथ सरकार एक नई यूनिवर्सिटी टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी लाने का प्रस्ताव सदन में रख रही है। आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैम्पस, डीटीयू और तमाम इन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंशन का काम भी जोरों पर है और उससे संबंधित अलग—अलग प्रोजेक्ट जिससे कि करीब चार हजार स्टूडेंट्स अलग—अलग उसमें, इनटेक में पढ़ेंगे, वो भी मैं इस सदन में समक्ष रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बाद दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना केज़रीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक दूसरा सबसे बड़ा आधार

रहा है। मोहल्ला क्लिनिक और आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पतालों के जरिये दिल्ली के हर नागरिक को क्वॉलिटी हैल्थ केयर देना मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दस गारंटियों में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को गवर्नेंस में सर्वोपरि रखे जाने का मुख्य मंत्री जी का विचार ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का दायित्व निभाते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई स्तरों पर पहल की और हर स्तर पर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। दुनिया भर से आने वाले भारतीयों के लिए कोरेंन्टाइन सुविधाएं युद्धस्तर पर उपलब्ध कराई गयीं। इसके लिए वर्तमान, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही संशोधित अनुमानों में तीन करोड़ की राशि का हमने प्रावधान किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इसमें किया है। मेरा सदन को आश्वासन है और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि भविष्य में भी इस महामारी से लड़ने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी, वो उपलब्ध कराई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 451 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोलकर दे चुकी है। 24 पॉली क्लिनिक और 36 मल्टीस्पेशलिटी, सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों के जरिये देखभाल की सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अप्रैल से दिसम्बर तक, दिसम्बर, 2019 तक लगभग 55 लाख नागरिकों को मोहल्ला क्लिनिकों के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं मिली जब कि सवा दो करोड़ रोगियों का उपचार दिल्ली सरकार के अस्पतालों और पॉलिक्लिनिक के माध्यम से हुआ। ये आधार है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, एजुकेशन, हैल्थ। अब सवा दो करोड़ जिनको फायदा मिला दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पतालों, हॉस्पिटल्स और पॉलिक्लिनिक से। मौजूदा चिकित्सालयों को उन्नत बनाकर 94 पॉलिक्लिनिक स्थापित किये जा रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ाकर एक हजार की जायेगी।

मैं मोहल्ला क्लिनिक और पॉलिक्लिनिक के लिए 365 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान करता हूं।

सरकार ने 10 हजार बिस्तरों की क्षमता बढाकर 26 हज़ार बिस्तर करने के लिए मौजूदा अस्पतालों को उन्नत बनाने और विस्तारित और नये अस्पतालों के निर्माण कार्य का शुरू कर दिया है। बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पतालों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और यह जल्दी ही फंक्शनल हो जायेंगे। द्वारका में अस्पताल का निर्माण काफी एडवांस स्टेज पर है। 2019–20 के संशोधित अनुमान में नये अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों के उन्नत बनाने के लिए 724 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है जब कि पिछली बार इसमें 195 करोड़ रुपये रखे गये थे। इसी से आप आज सोच सकते हैं कि नये हॉस्पिटल बनाने और पुराने हॉस्पिटल्स को रिन्यू, अच्छे उसमें गुणवत्ता बढ़ाने में, उनके बैड्स बढ़ाने में, कितना, 195 करोड़ रुपये से राशि बढ़ाकर 724 करोड़ रुपये की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आरोग्य कोष के जरिये उपलब्ध कराई जा रही फ्री ट्रीटमेंट सर्जरी, रेडियोलॉजी, डॉयग्नोस्टिक स्कीम और चिकित्सा उपचार अब मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के दायरे में आयेंगे। इस योजना में 1016 सर्जिकल पैकेज़ फ्री शामिल किये गये हैं, फ्री ट्रीटमेंट के लिये शामिल किये गये हैं।

मैं मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ जिसमें एक सौ करोड़ रुपये का प्रावधान दिल्ली आरोग्य कोष का भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए मुख्य मंत्री हेल्थ कार्ड योजना लेकर आ रही है। इसके तहत हैल्थ आईडी कार्ड तैयार किये जायेंगे और दिल्ली के सभी निवासियों को वितरित किये जायेंगे। हैल्थ आईडी कार्ड को सरकार के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पताल सूचना प्रबन्धन प्रणाली से जोड़ा जायेगा।

सरकार ने जो फेक डॉक्टर्स का... और जो सबकी प्राब्लम होती है; गैर पंजीकृत केंद्र और मशीनों के बारे में सूचना देने के लिए स्टिंग, डिकॉय ऑपरेशन के लिए पीसी और पीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत खबरी पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये और सच को सामने लाने के लिए रोगी बनने वाले को डेढ़ लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा। इससे हैल्थ की

क्वॉलिटी शहर में और सुधरेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और आम लोगों और विभिन्न पक्षों द्वारा अपेक्षित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक नाम से एक व्यापक अधिनियम पर भी काम कर रही है उसको भी इस सदन में लेकर आया जायेगा।

दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष, प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020–21 में 'आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना' को लागू करेगी।

मादक पदार्थ, विभाग ने नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनायी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने दिसम्बर 2019–20 तक तय नियमों का उल्लंघन करने वाली 32 निर्माण इकाइयों और 107 बिक्री परिवारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मैं 2020–21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,704 करोड़ रुपए का प्रावधान करताा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब जल आपूर्ति और स्वच्छता पर मैं अपनी बात रखूंगा। मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगले पांच साल के अंदर दिल्ली के हर घर को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल व्यवस्था करने की गारंटी दी है। देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिलना ही चाहिए, वो भी 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का अहम हिस्सा है। सरकार ने गारंटी कार्ड में दिए गए आश्वासन के अनुसार इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार को 20 हजार लीटर पानी की मुफ्त आपूर्ति भी अगले साल जारी रहेगी। इसकी तैयारी में जो 24 घंटे पानी की गारंटी है, इसकी तैयारी में पूरी दिल्ली में 3,341 बल्क वाटर मीटर लगवाए जा रहे हैं ताकि पानी का मैनेजमेंट ठीक से हो सके। ये सभी मीटर्स जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे, इसकी गारंटी है। इसके बाद पानी की मात्रा का हिसाब रखना, पानी की आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाना, समानता के आधार पर इसका बटवारा करना आसान हो जाएगा।

पानी बढ़ेगा कैसे? पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी के तट पर चार डिसैंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाए जाएंगे जिनकी क्षमता करीब चार एमजीडी की होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 इंस्टॉलेसन में से 439 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, अमल करना शुरू कर दिया है। 155 अन्य इंस्टॉलेशंस में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग इस साल स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, इससे पानी बढ़ेगा। 1605 अनधिकृत कालोनियों को पाइप लाइनों के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम के दायरे में लाया गया है, इनमें से 1539 कालोनियों में पानी की सप्लाई शुरू हो गयी है, 1605 में से 1539 में शुरू हो गयी है और 56 अन्य में पानी की आपूर्ति शुरू करने के बारे में जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 40 कालोनियों में काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 22 जलाशयों को पानी से फिर से लबालब करने के काम का ठेका दे दिया है, इसके लिए अवजल का शोधन कर, सीवर का ट्रीटमैंट कर पर्याप्त गुणवत्ता वाले पानी से इन तालाबों को भरा जाएगा। जलमल शोधन क्षमता बढ़ाकर 600 एमजीडी कर दी गई है और शोधन क्षमता का उपयोग 500 एमजीडी के स्तर पर भी हो रहा है। इन्टरसेप्टर, जलमल परियोजना के पूरी तरह लागू होने से क्षमता में निरंतर और बढ़ोत्तरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड सीवर लाइनों से रहित इलाकों में सीवर विस्तार के लिए मास्टर प्लान–2031 पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रहा है। 434 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर लाइनें बिछाकर इन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है। 597 अन्य कालोनियों में ये काम जारी है और इसे दिसम्बर, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दिल्ली जल बोर्ड ने 'मुख्य मंत्री सीवर कनैक्शन योजना' शुरू की है। यह ऐसे इलाकों के लिए है जहां सीवर लाइनें तो हैं लेकिन लोगों ने अपने घर के लिए कनैक्शन नहीं लिये हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 से पहले सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड अपने खर्च पर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा जिसमें स्थापना शुल्क, प्रारंभिक शुल्क, सड़क बहाली शुल्क और सीवर आवेदन पत्र की कीमत भी शामिल है, क्योंकि लोग उसकी वजह से कनेक्शन नहीं ले रहे थे।

यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर की एक यूनिक परियोजना का काम

98 परसेंट पूरा कर लिया गया है और नालों के करीब 141 एमजीडी अवजल की, सीवर शोधन संयत्रों में सफाई की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पावर सैक्टर पर बात रखूंगा, बिजली पर। आज देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने हर महीने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जीरो बिल बिजली योजना शुरू की थी, भले ही उनका स्वीकृत लोड कितना ही क्यों न हो। इसके अलावा 201 से 400 यूनिट मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, पूरी दिल्ली के करीब 90 परसेंट परिवारों में बिजली सब्सिडी का फायदा पहुंच रहा है। सब्सिडी योजना से बिजली के संरक्षण को बढ़ावा मिला है। ये भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है कि सब्सिडी योजना से बिजली के संरक्षण को बढ़ावा मिला है क्योंकि उपभोक्ता सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपनी खपत को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरकार सिखों के खिलाफ 1984 में हुए दंगों के पीड़ितों को बिजली की खपत 400 यूनिट तक सीमित रखने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देती है।

अदालत परिसरों के भीतर वकीलों के चैंबर्स के लिए भी विशेष बिजली सब्सिडी योजना का विस्तार कर उनको भी इसका फायदा दिया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषक उपभोक्ताओं को खेती वाले कनेक्शन के लिए नियत शुल्क में 105 रुपए प्रति किलोवाट से लेकर 20 रुपए प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती है। ये सब योजनाएं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा हैं, बहुचर्चित हिस्सा हैं और अगले वर्ष में भी जारी रहेंगी।

मैं विद्युत सब्सिडी 2020–21 के बजट में 2,820 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूं।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले लोगों, संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी इमारतों, स्कूलों, तकनीकि इन्स्टीट्यूशंस, न्यायालय आदि में सौर संयंत्र लगाने की कार्रवाई चल रही है।

दिल्ली में जनवरी, 2020 तक कुल 161.898 मैगावाट के लगभग, 3,579 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। किसानों ने मुख्य मंत्री किसान बढ़ोत्तरी सोलर योजना के अंतर्गत सौर बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन देने का भी प्रस्ताव किया है।

दिल्ली की बिजली कम्पनियॉ, इसके अलावा क्योंकि 24 घंटे बिजली आ रही है, देश की राजधानी में मिलनी भी चाहिए, उसमें बिजली कम्पनियॉ नैटवर्क क्षमता बढ़ाने, अपने एक्स्ट्रा लोड में एनहांस करने, बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओटोमेशन, इन सब काम पे लगी हैं। वितरण कम्पनियॉ दिल्ली के विभिन्न भागों में उलझे हुए बिजली के तारों को हटाने के लिए काम करेंगी ताकि इनसे जानमाल के लिए कोई खतरा न हो और शहर और भी सुंदर बने।

एन्वायरन्मेंट; अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबोहवा को साफ रखना और दिल्ली को हरा–भरा रखना मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में शामिल है। विभिन्न प्रयासों से वायु प्रदूषण को विगत पांच वर्ष में 25 परसेंट कम किया गया था। अगले पांच साल में हमारा लक्ष्य है, इसे दो–तिहाई और कम करना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने ओर इसमें जन भागीदारी के लिए पूरी दिल्ली में, सघन अभियान सरकार चलाएगी, इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

इसके तहत घर पर ही कूड़े–करकट की छंटाई, सिर्फ एक बार उपयोग में आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने, ग्रीन रूफ अवधारणा के तहत छतों पर पेड़–पौधे लगाने, गुलदस्ता भेंट करने की बजाय पौधे उपहार देने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग करने, कम दूरी के स्थानों को साइकिल से तय करने, पटसन और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने, कागज की बर्बादी रोकने, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्सव मनाने, पर्यावरण सम्मेलन आदि का भी आयोजन किया जाएगा। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण के कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन सिटिजन अवॉर्ड भी दिए जाएंगे, ये एक नई योजना लेके आएंगे ताकि ग्रीन योजना, नागरिक उसमें बढ़–चढ़ के भाग लें।

इसके साथ—साथ अभी तक जो पर्यावरण नियम कानून—कायदे रूल्स हैं, उनको पालन कराने का काम केवल एसडीएम्स या वन विभाग के अधिकारियों पे रहता है और उनके पास में श्रम शक्ति की कमी रहती है। इसके लिए मैं 2020—21 में पर्यावरण विभाग में एनवायर्न्मेंट मार्शल्स की नई योजना का प्रस्ताव करता हूं ताकि इस कार्य के लिए समर्पित श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही प्रदूषण को बड़े पैमाने पर दूर करने वाले स्मॉग टावर स्थापित करने की परियोजना पर भी अमल की जरूरत है। मैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली में हरित पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र और वृक्षों के दायरे में बढ़ोत्तरी के विभिन्न उपाए किए, पिछले पांच साल में और इनके परिणामस्वरूप वन और हरित क्षेत्र का दायरा 2015 के लगभग 300 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर, 2019 में लगभग 325 वर्ग किलोमीटर हो गया है, केवल पांच साल में 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। इस प्रकार कुल क्षेत्र की तुलना में हरित क्षेत्र बढ़कर 21.88 हो गया। अगले पांच साल में दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2020—21 में 22 हरित एजेंसियों द्वारा 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

पब्लिक ट्रांस्पोर्ट, महोदय 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के तहत मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गारंटी दी है। इसके तहत सरकार ने 11 हजार से अधिक बसें और 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मैट्रो लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है। करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में नई बसों का जुड़ना शुरू हो हुआ है। सरकार की दूरदर्शी योजना के तहत आधुनिक सीसीटीवी युक्त और शायद देश में पहली बार 'डिस्एेबल्ड फ्रेंडली लिफ्ट' वाली बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की गयी हैं। कॉमनवैल्थ खेलों के आयोजन के बाद पहली बार नई लो—फ्लोर बसें अब दिल्ली के परिवहन बेड़े में शामिल हो रही हैं। कुल मिलाकर 2,485 नयी बसें, वर्ष 2020—21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1880 बसें, जिसमें 444 डीटीसी

और 1,436, 2021–22 में खरीदी जाएंगी। इस तरह 11 हजार बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए 250 करोड़ रुपए और क्लस्टर बसों में वाएबिल्टी गैप फंडिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां ये भी सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली में जमीन की उपलब्धता न होने के कारण बसों को खरीदना और उन्हें संचालित करना एक बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अब सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए औखला, हरीनगर, वसंत विहार और हसनपुर के डिपो सहित चार डिपो को मल्टीलेवल बस डिपो में बदलने का प्रस्ताव किया है, फैसला किया है और ये शायद अपनी तरह के देश में पहले मल्टीलेवल डिपो का मॉडल खड़ा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की आर्थिक सक्षमता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2019 से उन्हें डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कराने की सुविधा प्रदान की थी। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली करीब 6,500 बसों में महिलाएं निःशुल्क आने–जाने में सक्षम हुई हैं, ये योजना अगले साल भी जारी रहेगी।

मैट्रो के तीसरे चरण में अतिरिक्त कॉरीडोर बनाने और एनसीआर में इसके 158 किलोमीटर विस्तार का काम पूरा हो चुका है। दो किलोमीटर का बकाया कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार ने मैट्रो फोर्थ फेज के सभी छः कॉरीडोर को मंजूरी दी है, लेकिन भारत सरकार ने अभी मैट्रो चतुर्थ परियोजना के पैकेज में से प्राथमिकता वाले तीन कॉरीडोर; जनकपुरी– आर.के.आश्रम, एयरोसिटी–तुगलकाबाद और मुकुंदपुर–मौजपुर को ही मंजूरी दी है। चौथे चरण हेतु डीएमआरसी को 200 करोड़ रुपए 2018–19 में दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान में इस वर्ष 1324 करोड़ रुपए आबंटित किए गए है। मैं 2020–21 में 900 करोड़ रुपए के परिव्यय का भी प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ई–व्हीकल पॉलिसी को 2019 में स्वीकृति प्रदान की। इसमें पुराने वाहनों के स्थान पर नए ई–व्हीकल्स की खरीद को बढ़ावा

देना है ताकि परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन, पॉल्यूषन में कमी आए और इससे दिल्ली की वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। मैं राज्य विद्युत चालित वाहन निधि के लिए 2020–21 में 50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

इसके अलावा कई रोड परियोजनाएं भी हैं। आईआईटी से एनएच–8 तक के कॉरीडोर्स सुधार योजना के हिस्से के रूप में मुनिरका पेट्रोल पम्प से लेकर केन्द्रीय बस पोस्ट ऑफिस तक तीन लेन का फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। इसका दूसरा चरण इनर रिंग रोड, वेनिता हुआरेज मार्ग और सान मार्तिन मार्ग के जंक्शन पर दो लेन वाले अंडरपास का निर्माण जून, 2020 में पूरा हो जाएगा। पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुसार एनएच–10 पर रामपुरा, त्रिनगर, इंद्रलोक और कर्मपुरा दिल्ली में पुलों को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। करीब 20 परसेंट काम पूरा कर लिया गया है और बाकी परियोजना इस साल पूर्ण कर ली जाएगी।

मैंने अपने पिछले बजट में एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे, हर विधान सभा में करीब 2 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की थी। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि एक लाख 32 हजार सीसीटीवी कैमरे पहले स्थापित किये जा चुके हैं और अब हमारी सरकार ने आरडब्लूए और मार्केट एसोसिएशन में लगाए जाने वाले कैमरों समेत इनकी संख्या एक लाख 40 हजार से बढ़ाकर दो लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे कर दी है। एक लाख 40 हजार सीसीटीवी लगाने का द्वितीय चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 2020–21 में ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020–21 में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी सभी स्ट्रीट लाइट्स को बदलेगी और उनकी जगह बिजली की किफायत करने वाली एलईडी लाइट लाएगी। इससे स्ट्रीट लाइटों की संचालन लागत छः करोड़ प्रतिमाह से घटकर तीन करोड़ प्रतिमाह रह जाएगी, ऐसा अनुमान है। इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये होगी और इसका कार्य 2020–21 में शुरू कर दिया जाएगा।

आम जनता को वाई–फाई के निःशुल्क इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध कराने

को सरकार कमिटेड है। ये मुख्य मंत्री जी का एक गवर्नेंस का बड़ा वादा था। इसके लिए 11 हजार हॉट स्पॉट का काम शुरू कर दिया गया है। इनमें से करीब दो हजार वाई–फाई हॉट स्पॉट काम कर रहे हैं।

सड़कों पर यातायात में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। शहरीकरण में आ रही तेजी और यातायात घनत्व बढ़ने से सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सड़कों की भौगोलिक स्थिति, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं और चौराहों के गोल चक्कर में सुधार की आवश्यकता है। मैं इस कार्य के लिए अलग से 193 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नई योजना 'सड़क अवसंरचना में सुधार' का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है और इसमें विकास का कार्य फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। इसके अंतर्गत उनमें बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे सड़क, नाली, पानी की आपूर्ति, जलमल और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। अनाधिकृत कॉलानियों में विकास कार्यों के लिए धनराशि, डीजेबी, डीएसआइडीसी और आइएफसी जैसी एजेंसीज को दी जाती है। अब तक दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1281 में विकास कार्य पूरे हो गये हैं या चल रहे हैं। 2020–21 के अंत तक सभी कॉलोनियों में विकास कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं अनअथोराइज कॉलोनीज में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट अनुमान 2020–21 में 1700 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं जब कि पिछले साल ये 1520 करोड़ रुपये का आबंटन था।

स्थानीय नागरिक, स्थानीय स्तर पर सामान्य विकास के पूरक के रूप में और इसमें हो रही कमियों को दूर करने के लिए बजट अनुमान में 400 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नई योजना 'मुख्य मंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास' का प्रस्ताव किया गया है जो वर्तमान 'मुख्य मंत्री सड़क पुनरोत्थान योजना' के साढ़े चार सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी।

दिल्ली के हर गली–कूचे में जनता की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान रखने के

लिए 2020–21 में 100 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'मुख्य मंत्री मोहल्ला सुरक्षा' नाम की योजना का प्रस्ताव भी किया गया है ताकि इसमें बहुत सारे लोग गेट की मांग करते हैं और इस तरह की सुरक्षा की और योजनाएं हैं। सीसीटीवी वगैरह तो पहले ही लग रहे हैं, उनको भी मुख्य मंत्री जी की ओर से आश्वासन है कि हम गेट भी लगवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ड्यूसिब और दिल्ली सरकार की जमीन पर बनी झुग्गी बस्तियों में से ड्यूसिब द्वारा हाल में कराये गये मांग सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी कॉलोनीज में रहने वाले 65 हजार परिवारों को सर्वेक्षण प्रमाण–पत्र दे दिये गये हैं। ड्यूसिब झुग्गी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास का कार्य करता है और उन्हें रहने योग्य निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की तरह फ्लैट उपलब्ध कराकर इज्जत से जिन्दगी जीने का मौका देता है। 'जहां झुग्गी, वहां मकान' योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्के मकान उपलब्ध कराकर बसाने का वादा किया है ताकि उनकी आजीविका संबंधी गतिविधियों में किसी तरह का व्यवधान न आये। हमारी सरकार ने इस सिलसिले में 11 दिसम्बर, 2017 को 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के बारे में अधिसूचना जारी की थी। इसके लिए पुनर्वास की पात्रता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 01 जनवरी, 2015 की गयी, इससे झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले 90 परसेंट लोग फ्लैट पाने के पात्र हो जाएंगे। ड्यूसिब अपनी और दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी 138 मौजूदा झुग्गी बस्तियों को पांच किलोमीटर के दायरे में शौचालय, स्नानागार, रसोई से युक्त दो कमरों के फ्लैटों में स्थानांतरित करेगा। ये फ्लैट ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की तर्ज पर बनाये जाएंगे।

मैं 2020–21 के लिए आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए कुल 3,544 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 1415 करोड़ रुपये राजस्व और 2129 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च शामिल है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए यमुना नदी, नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और शाहदरा नाले जैसे अनेक नालों से प्रदूषित हो रही है। हमारी सरकार

इन नालों को साफ करने और इनके सौंदर्यकरण के प्रयास करेगी। यमुना को साफ सुथरा करना भी 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के तहत मुख्य मंत्री केजरीवाल जी की गारंटियों में शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान हम यह कार्य नजफगढ़ नाले से आरम्भ करेंगे, इसके तहत ढांसा बॉर्डर से बसई दारापुर तक 45 किलोमीटर भूजल का स्तर बढ़ाने और सतह की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए उसकी गाद निकालने, नालों को गहरा करने, बांध, बैराज बनाने का काम किया जाएगा। नजफगढ़ नाले के किनारे की खाली जमीन पर पार्क और मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी उपाय अगले तीन साल में पूरे कर लिये जाने की आषा है और इन पर दो हजार करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान है। मैं 2020–21 में तटबंध योजना के अंतर्गत इस कार्य के लिए 410 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट में दिल्ली में भूजल स्तर में सुधार और सतत जल उपलब्धता के लिए एक हजार एकड़ क्षेत्र में बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए पल्ला एरिया में जलाशय के निर्माण की योजना घोषित की थी। इस संबंध में यमुना बाढ़ क्षेत्र में वजीराबाद के ऊपर धारा के अतिरिक्त जल संचय के लिए 40 एकड़ क्षेत्र में जलाषय निर्माण की पायलट परियोजना अगस्त, 2019 में शुरू की गयी। इसका आंषिक कार्य 17 एकड़ में पूरा हो चुका है, शेष कार्य 2020 में पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020–21 में इस बजट के लिए, इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन 2017 में दिल्ली के गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने अपने गठन के बाद से 1235 करोड़ रुपये लागत की कुल 1029 योजनाओं को मंजूरी दी, इसमें से 505 करोड़ रुपये के काम 458 निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए दे दिये गये हैं। 193 कार्य पूरे किये जा चुके हैं और गांवों में 183 का काम चल रहा है, जो 2020–21 में पूरे हो जाएंगे।

मैं 2020–21 के बजट में दिल्ली गांवों के विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी जिक्र किया कि 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' में 'केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स' बार–बार उभर के आता है। एजुकेषन, हैल्थ और बाकी आम आदमी के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ–साथ और मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुषी हो रही है कि नीति आयोग द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक की दृष्टि से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेषों में शीर्ष स्थान पर है, इसे 100 अंक मिले है जबकि अखिल भारतीय औसत 65 का है।

दुनिया भर में दिल्ली की ख्याति स्टार्टअप्स के केंद्र के रूप में है। सरकार दिल्ली के लिए नई स्टार्टअप नीति को अंतिम रूप देने में लगी है और एक नई इनक्यूबेषन सेंटर स्थापित करने जा रही है। सरकार ने एक महा आयोजन शुरू करने की भी योजना बनाई है जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा ताकि स्टार्टअप्स वाले माहौल में सभी सम्बद्ध पक्ष नये–नये विचारों और टेक्नोलॉजी के बारे में विचारों का आदान–प्रदान कर सकें। इसका मूल उद्देष्य स्टार्टअप कम्पनियों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। बजट अनुमान 2020–21 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप समारोह के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह दिल्ली इन्नोवेषन सेंटर एक सरकार की ओर से बनाया जाएगा और उसे बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित दिल्ली एम्पोरियम में 7,476 वर्ग फुट कॉर्पेट क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये स्टार्टअप आधुनिक सुविधाओं जैसे कान्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, वीडियो कान्फ्रेसिंग, तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा, वाई–फाई सम्पर्क और मेंटर, स्टार्टअप में मेंटर का बहुत महत्व होता है, मेंटर की सहायता हासिल करने के लिए, साथ काम करने की जगह और इसी तरह की तमाम सामान्य कारोबारी सेवाओं से सुसज्जित होगा।

लेबर, मजदूरों के लिए सरकार बहुत चिंतित रहती है। हमारी सरकार काम करने के माहौल में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाने की दिषा में काम कर रही है ताकि श्रमिक शोषण का षिकार हुए बिना इज्जत के साथ काम कर सकें। दिल्ली में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को नियमित करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बिल 2019, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, श्रम

कानूनों के दायरे से बाहर पल्लेदार और इसी तरह के अन्य श्रमिकों के संरक्षण और लाभ के लिए दिल्ली मथाड़ी पल्लेदार और अन्य असंरक्षित श्रमिक विधेयक भी लेकर आयी।

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के कार्यक्रमों में सरकार हमेषा आगे रही है और महिलाओं की सुरक्षा, जैसा इस बजट में अभी तक बार—बार आया, मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल में सबसे ऊपर रहा है और उसको आगे बढ़—चढ़के मुख्य मंत्री जी ने खुद उसको लीड किया है। तो 2020—21 में 20 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'व्यवहार परिवर्तन' नाम की एक नई योजना का प्रस्ताव है ताकि जो समाज में सोच है, उसको भी बदला जा सके। सोच के बदलने पे काम हो सके। इसके अंतर्गत समाज में व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, तत्काल आवष्यक चिकित्सकीय उपचार, सामान्य इलाज, स्ट्रोक या किसी अन्य बीमारी होने, स्थायी या आंषिक विकलांगता उत्पन्न करने वाली दुर्घटना के मामलों के लिए मैं 2020—21 में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक नई 'मुख्य मंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना' का प्रस्ताव करता हूं।

'जय भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना' का विस्तार किया गया है और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के साथ—साथ दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्र—छात्राओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध 46 कोचिंग संस्थानों के जरिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःषुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना के तहत 47 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग पिछले साल दी गई जिनमें से 13 ने जेई मुख्य परीक्षा के लिये क्वालिफाई किया जिनमें से तीन को आईआईटी, एनआईटी और एनएसयूटी में दाखिला मिला। 58 स्टूडेंट्स को मैडिकल प्रवेश परीक्षा के लिये कोचिंग दी गई और इसमें से 22 ने एनईटी परीक्षा के लिये क्वालिफाई किया।

मैं 2020—21 में इस परियोजना के लिये 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का

प्रस्ताव करता हूं जबकि पिछले वर्ष ये, इसके लिये 17 करोड़ रुपये रखे गये थे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान के रूप में मुख्य मंत्री तीर्थयात्रा योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत वे देश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा कर पाते हैं। सरकार ने भविष्य में भी इस योजना को जारी रखने और अगले पांच साल में दस लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा देने का आश्वासन दिया है।

मैं वर्ष 2020—21 के बजट में मुख्य मंत्री तीर्थयात्रा योजना के लिये 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखता हूं।

इसके साथ—साथ दिल्ली दर्शन योजना भी एक शुरू की जायेगी, उसके लिये भी दस करोड़ का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें दिल्ली भ्रमण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ऐडवोकेट वेल्फेयर फंड योजना के तहत दिल्ली के निवासी और वकालत करने वाले पंजीकृत वकीलों को मैडिक्लेम पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंश पॉलिसी, ई लायब्रेरी और क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

इसके लिये अगले वित्त वर्ष में भी 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

मैं सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिये 2020—21 में कुल चार हजार चार सौ 66 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखता हूं, इसमें विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये तीन 3868 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ—साथ दिल्ली को, दिल्ली में नये जॉबस क्रिएट करने और दिल्ली को एक टूरिस्ट ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिये भी सरकार योजना ले के आ रही है। दिल्ली के अंदर देश की टूरिज्म कैपिटल का सैन्स डेवलेप हो, उसकी संभावनाए बहुत हैं। संसाधन हैं, हैरिटेज मॉन्यूमेंट से ले के आधुनिक बाजार तक हैं। पुरानी दिल्ली की परम्पराएं हैं, नाइट लाइफ है, देश विदेश के

पर्यटक इसके लिये आकर्षित होकर आते हैं लेकिन ब्राडिंग और जानकारी के अभाव में ज्यादातर टूरिस्ट दिल्ली को एक ट्रांजिशन प्वाइंट के रूप में यूज करते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में आने वाला टूरिस्ट औसतन एक दिन दिल्ली में बिताता है, जो टूरिज्म है दिल्ली में, उसको ये माना जाता है कि एक दिन एक टूरिस्ट दिल्ली में रुकता है ऐवरेज, जबकि लंदन, सिंगापुर और टोकियो जैसे शहरों में एक टूरिस्ट औसतन तीन दिन बिताता है। दिल्ली सरकार योजना बना रही है कि दिल्ली आने वाला हर टूरिस्ट दिल्ली में कम से कम दो दिन ऐवरेज जरूर बिताये। केवल एक दिन के फर्क से दिल्ली में लाखों नये रोजगार होंगे और अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी के नये अवसर पैदा होंगे। इस योजना से दिल्ली के टूरिज्म की रिब्राडिंग की जायेगी और देशी व विदेशी पर्यटक तक देश विदेश में दिल्ली को एक टूरिज्म ब्रांड के रूप में पेश किया जायेगा। दिल्ली आने वाले हर जो देशी विदेशी पर्यटक वो चाहे रेलवे स्टेशन पर आयें या हवाई अडडे पर, उन्हें दिल्ली को जानने और दिल्ली को घूमने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

दिल्ली के डॉयनेमिक स्वरूप को दिल्ली के टूरिज्म का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में सरकार पहले से काम कर रही है। पिछले वर्ष बिना पटाखे जलाये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से दीवाली मनाने की पहल की गई और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ लेजर शो का आयोजन किया गया, इसकी व्यापक सराहना हुई और दिल्ली के लोगों को एक अच्छा संदेश गया। दिल्ली की दीवाली का आयोजन अगले साल भी होगा। इसी के साथ साथ अगले साल पूर्वांचल उत्सव के नाम से भी एक नया उत्सव दिल्ली में शुरू करने का प्रस्ताव है।

हाल ही में हुई सांम्प्रदायिक हिंसा के बाद ये जरूरत महसूस की गई है कि लोगों में सांम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने के लिये अतिरिक्त प्रयास किये जायें और इसके लिये 'कैम्पेन फार कम्यूनल हार्मनी' की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, ये मूलरूप से अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों का सार है जिसमें योजनाओं का सार है। मेरे बजट वक्तव्य में अगला हिस्सा भाग 'ख' है जो मूल रूप

से तकनीकी है, मैं इसको भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इसे पढ़ा हुआ माना जाने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, एक बार फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग दुनिया में कोरोना की महामारी का शिकार हैं या संभावित हैं, ईश्वर उनको स्वास्थ्य प्रदान करे और मानव जाति को इस महामारी से बचाकर रखें और उन लोगों के लिये खास तौर पर क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है, आज आपने 15 बोला था, अभी लेटेस्ट जानकारी जो मुझे मिली कि शायद 24 राज्यों ने लॉकडाउन घोषित किया है। तो इस सब के दौरान जो लोग फिर भी ये मानते हैं कि कोरोना मुझको नहीं हो सकता है, उन सबको भी सदबुद्धि दे ईश्वर और उनको वशीरबद्र साहब के एक शेर के साथ मैं बात खत्म करता हूं किः

कोई हाथ भी ना मिलायेगा,

जो गले मिलोगे तपाक से,

ये नये मिजाज का शहर है,

जरा फासले से मिला करो।

बहुत बहुत धन्यवाद।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण,
विचार एवं पारण। (वित्त वर्ष 2019–20)

माननीय अध्यक्षः अब माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2019–20 के लिये सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश करेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I present third and final batch of supplementary Demands for Grants for the year 2019-20 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा।

डिमांड नंबर–दो, (जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन):

जिसमें रेवेन्यू में एक लाख रूपये हैं, सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–दो पास हुई।

डिमाण्ड नंबर–चार, (फाइनेंस):

जिसमें रेवेन्यू में 1 लाख रूपये हैं, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–चार पास हुई।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–छः, (ऐजुकेशन):

जिसमें रेवेन्यू में 27 लाख रुपये तथा कैपिटल में 2 लाख रुपये हैं, कुल राशि 29 लाख रुपये है, सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–छः पास हुई।

डिमाण्ड नंबर–नौ, (इंडस्ट्रीज):

जिसमें रेवेन्यू में 4 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–नौ पास हुई।

डिमाण्ड नंबर–दस, (डेवलेपमेंट):

जिसमें रेवेन्यू में 15 लाख, 15 हजार रुपये तथा कैपिटल में 1 लाख रुपये, कुल राशि 16 लाख, 15 हजार रुपये है, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–दस पास हुई।

सप्लीमेंटरी डिमाण्ड नंबर–ग्यारह, (अर्बन डेवलेपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स):

जिसमें रेवेन्यू में 5 लाख रुपये तथा कैपिटल में 5 लाख रूपये, कुल राशि 10 लाख रुपये है, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

हाऊस ने कुल मिला कर रेवेन्यू में 84 लाख, 15 हजार, रुपये तथा कैपिटल में 13 लाख, कुल राशि 97 लाख, 15 हजार रुपये की सप्लीमैंटरी डिमाण्ड को मंजूरी दे दी है।

विनियोजन (संख्या–1) विधेयक, 2020

एप्रोप्रिएशन (नंबर–वन), बिल 2020, (बिल नंबर वन ऑफ 2020), अब माननीय उप मुख्य मंत्री एप्रोप्रिएशन (नंबर–वन), बिल 2020, (बिल नंबर एक– 2020) को हाऊस में इन्ट्रोडयूस करने की परमीशन मांगेगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce appropriation (No. 1) (Bill 2020, (number one of 2020) to the House.

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री बिल को सदन में इंट्रोडयूस करेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I introduced appropriation (No. 1) Bill 2020, Number One Bill of 2020 to the House.

माननीय अध्यक्षः अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड दो, खंड तीन व शेड्यूल बिल का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड–दो, खंड–तीन एंव शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि–खंड–एक, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बने,

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड–एक, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एप्रोप्रेशन (नंबर वन), बिल 2020, (बिल नंबर वन ऑफ 2020) को पास किया जाये।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 1) Bill, 2020. Bill No. One of 2020.

माननीय अध्यक्ष: माननीय उप मुख्य मंत्री का प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

एप्रोप्रिएशन (नंबर वन) बिल 2020, (बिल नंबर वन ऑफ 2020) पास हुआ।

अनुदानों की मांगें (वित्त वर्ष 2020–21)

अब माननीय उप मुख्य मंत्री वित्त वर्ष 2020–2021 के लिये डिमाण्ड्स फॉर ग्रांटस पेश करेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I present Demands for Grants for the year 2020-2021 before the House.

माननीय अध्यक्षः अब सदन डिमाण्डस फॉर ग्रांटस पर डिमांड वाइज विचार करेगा।

डिमाण्ड नंबर–एक, (लेजिस्लेटिव असेंबली)ः

जिसमें रेवेन्यू में 58 करोड़ 35 लाख रुपये है, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर वन पास हुई ।

डिमाण्ड नंबर–दो, (जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन)ः

जिसमें रेवेन्यू में 9 अरब, 18 करोड़, 98 लाख, 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नबर–तीन, (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस):

जिसमें रेवेन्यू में 11 अरब, 29 करोड़, 53 लाख रुपये हैं तथा कैपिटल में 10 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 11 अरब, 39 करोड़, 53 लाख रुपये सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नंबर–तीन पास हुई।

डिमाण्ड नंबर–चार, (फाइनेंस):

जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब, 15 करोड़, 58 लाख रुपये हैं तथा कैपिटल में 2 अरब, 66 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 5 अरब, 81 करोड़, 58 लाख रुपये सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नंबर–चार पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर–पांच, (होम):

जिसमें रेवेन्यू में आठ अरब 6 करोड़ 77 लाख रुपये तथा कैपिटल में 1 अरब 15 करोड़ 30 लाख रूपये, कुल राशि 9 अरब 22 करोड़ 7 लाख रुपये सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर– पांच पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर–छः, (एजूकेशन):

जिसमें रेवेन्यू में एक 133 अरब 49 करोड़ 38 लाख रुपये है तथा कैपिटल में 3 अरब 88 करोड़ 14 लाख रूपये, कुल राशि 137 अरब, 37 करोड़, 52 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नं0 6 पास हुई।

डिमान्ड नम्बर–सात, (मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ):

जिसमें रेवेन्यू में 63 अरब 30 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपये है तथा कैपिटल में 2 अरब 82 करोड़ 14 लाख रुपये है, कुल राशि 66 अरब, 12 करोड़, 56 लाख, 40 हजार रुपये सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर– सात पास हुई।

डिमान्ड नम्बर– आठ, (सोशल वेल्फेयर):

जिसमें रेवेन्यू में 84 अरब, 58 करोड़, 13 लाख रुपये है तथा कैपिटल में 16 अरब, 50 करोड़, 86 लाख रूपये, कुल राशि 101 अरब, 8 करोड़ 99 लाख रुपये सदन के सामने है:–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–आठ पास हुई।

डिमान्ड नम्बर– नौ, (इण्डस्ट्रीज):

जिसमें रेवेन्यू में 5 अरब 22 करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपये है तथा कैपिटल में 3 करोड़ 22 लाख रूपये, कुल राशि 5 अरब 26 करोड़ 11 लाख 50 हजार रुपये सदन के सामने है:–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–9 पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर– दस, (डेवलपमेन्ट):

जिसमें रेवेन्यू में 30 अरब 62 करोड़ 8 लाख 21 हजार रुपये हैं तथा कैपिटल में 10 अरब 15 करोड़ 93 लाख रूपये, कुल राशि 40 अरब 78 करोड़ 1 लाख 21 हजार रुपये सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–10 पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर– ग्यारह, (अर्बन डेवलपमेन्ट एण्ड पब्लिक वर्क्स):

जिसमें रेवेन्यू में 97 अरब 43 लाख 84 हजार रुपये हैं तथा कैपिटल में 96 अरब 84 करोड़ 34 लाख रूपये, कुल राशि 193 अरब 84 करोड़ 77 लाख 84 हजार रुपये सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–ग्यारह पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर– बारह, (लोन्स):

जिसमें कैपिटल में 1 करोड़ 50 लाख रुपये हैं, सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–बारह पास हुई।

डिमाण्ड नम्बर–तेरह, (पेन्शन्स):

जिसमें रेवेन्यू में 3 करोड़ रुपये हैं, सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

डिमाण्ड नम्बर–तेरह पास हुई।

हाउस में कुल मिलाकर रेवेन्यू में 446 अरब 55 करोड़ 56 लाख 45 हजार रुपये तथा कैपिटल में 134 अरब 17 करोड़ 43 लाख रूपये, कुल राशि 580 अरब 72 करोड़ 99 लाख 45 हजार रुपये की डिमाण्ड को मंजूरी दे दी है।

विनियोजन (संख्या– 2) विधेयक, 2020

अप्रोप्रिएशन (नम्बर 2) बिल, 2020, बिल नम्बर 2 ऑफ 2020, माननीय उप मुख्य मंत्री अप्रोप्रिएशन नम्बर 2, बिल 2020, बिल नम्बर 2 ऑफ 2020 को हाउस में इन्ट्रोड्यूस करने की परमीशन मांगेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce appropriation (No. 2) Bill 2, 2020 to the House.

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री जी का यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं:–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I introduced appropriation (No. 2), Bill 2, 2020 to the House.

माननीय अध्यक्षः अब बिल पर क्लॉजवाइज विचार होगा।

प्रश्न हैं कि खण्ड–दो, खण्ड–तीन व शेड्यूल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खण्ड–दो, खण्ड–तीन एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गये।

प्रश्न हैं कि खण्ड–एक, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खण्ड–एक, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गये।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एप्रोप्रियेशन (नम्बर 2), बिल 2020, (बिल नम्बर 2, 2020) को पास किया जाये।

Hon'ble Deputy Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the appropriation (No. 2) (Bill 2, of 2020).

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने हैः–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, न कहें,

(सामुहिक स्वर हां पक्ष में होने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

एप्रोप्रिएशन नम्बर 2, बिल ऑफ 2020,(बिल नम्बर 2 ऑफ 2020) पास हुआ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अब माननीय शहरी विकास मंत्री, श्री सत्येन्द्र जैन जी अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य सूची में दर्शाये गये दस्तावेज की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दू क्रमांक 3 के उपबिन्दू–एक में दर्शाये गये निम्नलिखित दस्तावेजों[6] की प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूंः

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वर्ष 2018–19 के वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी प्रति।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय परिवहन मंत्री, श्री कैलाश गहलौत जी अपने विभाग से सम्बन्धित कार्य सूची में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय परिवहन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिन्दू क्रमांक–तीन के उप बिन्दू–दो में दर्शायी गयी निम्नलिखित अधिसूचना[7] की अंग्रेजी, हिन्दी प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूंः

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संषोधित) के तहत कंपाउंड यातायात अपराधों के लिए निर्दिष्ट राषि के साथ अधिकारियों के प्राधिकरण के बारे में अधिसूचना संख्या एफ. (95)/परिवहन/ सचि./10/20110 दिनांक 13.03.2020 की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण जैसा आपको विदित है, मैंने वित्तीय समितियों के चुनाव की प्रक्रिया को जो पहले जारी की गयी थी, को स्थगित करने का फैसला किया गया है कोराना के कारण। नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं सदन के

6 पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20809 पर उपलब्ध

7 पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20810 पर उपलब्ध

नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी, सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए विधान सभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ विभिन्न विभागों एवं सुरक्षा एजेन्सियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। विशेषकर पीडब्लूडी के अधिकारियों का, विधान सभा सभागार को सैनेटाइजेशन करने में सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब राष्ट्र गान के लिए अपने–अपने स्थान पर खड़े हो।

...(राष्ट्रगान जन–गण–मन)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गयी।)

...समाप्त...

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शासन अधिनियम,1991 की धारा 18 (2) के उपबंधो तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, स्मैट फॉर्म्स, नई दिल्ली–110007 दृारा मुद्रित।